

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 30 जून, 2010

विषय:

चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वाह्य सहायतित स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद चमोली की मालबजवाड देवलकोट पेयजल योजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 459/एसडब्लूएसएम डीपीआर फाईल/प2009-10 दिनांक 31 मार्च 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैप आधारित जनपद चमोली की मालबजवाड देवलकोट पेयजल योजना के शासन को प्राप्त कराये गये अनु0लागत रू0 103.88 लाख के प्राक्कलन पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 96.57 लाख (रू0 छियानवे लाख सत्तावन हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही शासनादेश संख्या 562/उन्तीस(2)/10-2(37पे0)/08 दिनांक 14.06.10 द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में अवमुक्त रू0 30.00 करोड़ में से वाह्य सहायतित कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में रू0 96.57 लाख (रू0 छियानवे लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 2- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- 3- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- 4- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।
- 6- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- 7- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 8- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भलीभाँति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- 9- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

..2..

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

11- योजनाओं की स्वीकृत लागत में किसी प्रकार का सेन्टेज देय नहीं होगा।

12- व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/ फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली

जायेगी। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

15- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करें।

16- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2010 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 197/XXVII(2)/2010, दिनांक 23 जून 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0एच0खान)
सचिव

संख्या- 845/उन्तीस(2)/10-2(04पे0)/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मण्डलायुक्त गढ़वाल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।
- 4- वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- 5- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
- 6- वित्तअनुभाग-2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- संयुक्त विकास आयुक्त गढ़वाल।
- 8- आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
- 9- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्राक्कलन में हुई कटौतियों को नोट कर लें।
- 11- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- 12- निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 13- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14- गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव